सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

RNI No: UPHIN/2023/86769

www.swarajindianews.com

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

मूल्यः ₹ 02

स्वराज इंडिया

सांध्यकालीन समाचार पत्र

कानपुर, शनिवार, 24 मई, 2025
वर्षः 02, अंकः 146, पृष्ठः 8+4

यूपी के मुख्य सचिव को नोटिस

» Pg 12

इनसाइड भतीजों से अफेयर वाली चाची देखती थी गंदी फिल्में » Pg 03

देश का पहला बुलेट रेलवे स्टेशन तैयार

2029 से दौड़ेगी ट्रेन, भारत अब हाई-स्पीड रेल के युग में तेजी से करेगा प्रवेश

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

मुंबई-अहमदाबाद। बुलेट ट्रेन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अब इंतजार की घडियां बहुत जल्द खत्म होने वाली है क्योंकि भारत की पहली बुलेट ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में बताया कि इस मेगाप्रोजेक्ट के तहत 300 किलोमीटर लंबा वायाडक्ट बनकर तैयार हो चुका है। साथ ही गुजरात के सूरत के पास 40 मीटर लंबा बॉक्स गर्डर भी सफलतापूर्वक स्थापित किया जा चुका है।

दरअसल, भारत की बहुप्रतीक्षित पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनकर तैयार हो गई है। रेल मंत्री के अलावा विभिन्न राज्यों के परिवहन मंत्रियों ने भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ी तस्वीरें और प्रगति रिपोर्ट सोशल मीडिया पर साझा की हैं। यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

300 किलोमीटर के वायाडक्ट में से 257.4 किलोमीटर निर्माण 'फुल स्पैन लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी' से किया गया है, जो

पारंपरिक तकनीकों की तुलना में 10 गुना तेज निर्माण की सुविधा देती है। इस तकनीक में इस्तेमाल किए गए स्पैन गर्डर का वजन लगभग 970 टन होता है। इसके अलावा कई नदी पुल, स्टील और पीएससी ब्रिज, और स्टेशन बिल्डिंग्स का निमाज़्ण भी पूरा हो चुका है।

बता दें कि अब तक परियोजना के अंतर्गत 383 किमी पियर्स, 401 किमी फाउंडेशन और 326 किमी गर्डर कास्टिंग पूरी हो चुकी है। गुजरात में 157 किलोमीटर तक ट्रैक बेड भी बिछाया जा चुका है। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर कुल 12 आधुनिक स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इनमें से सूरत स्टेशन भारत का पहला पूर्णतः विकसित बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा, जिसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। शेष स्टेशनों का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है।

इस हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट में प्रयोग हो रही अधिकतर तकनीक और उपकरण भारत में ही

बनाए गए हैं। लॉन्चिंग गैंट्री, ब्रिज गैंट्री, गडज़र ट्रांसपोर्टर जैसे भारी-भरकम मशीनरी भारत में विकसित की गई है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि भारत अब हाई-स्पीड रेलवे टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। शोर को कम करने के लिए वायाडक्ट के दोनों ओर 3 लाख से अधिक नॉइज़ बैरियर्स लगाए गए हैं, जिससे यात्रियों को एक आरामदायक और शांत यात्रा अनुभव मिल सके।

2026 में हो सकता है ट्रायल रन

अगर निर्माण कार्य इसी गति से चलता रहा, तो 2026 तक सूरत से बिलीमोरा के बीच बुलेट ट्रेन का ट्रायल रन शुरू हो सकता है। रिपोर्ट्सज़ के अनुसार, अगस्त 2026 तक इस रूट पर ट्रेन संचालन की संभावना जताई जा रही है। वहीं 2029 तक इस प्रोजेक्ट के पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है। अगले साल की शुरुआत में जापान से शिंकानसेन बुलेट ट्रेन के कोच भी भारत पहुंच सकते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की लगातार निगरानी कर रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से नियमित अपडेट शेयर कर रहे हैं। उनके मुताबिक, यह न सिफ़्र भारत की पहली बुलेट ट्रेन होगी, बल्कि यह देश को गति, तकनीक और आधुनिकता की नई दिशा में ले जाएगी।

जापान दोस्त भारत को गिफ्ट करेगा दो बुलेट ट्रेन

जापान, भारत को दोस्ती का तोहफा देने जा रहा है। यह तोहफा है दो शिंकानसेन ट्रेन सेट। इन ट्रेनों का उपयोग मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के निरीक्षण के लिए किया जाएगा, जिनके 2026 तक भारत पहुंचने की उम्मीद है। बुलेट ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है। जापान, भारत को दोस्ती का तोहफा देगा। वह भारत को दो शिंकानसेन ट्रेन सेट देगा। ये ट्रेनें ई5 और ई3 मॉडल की होंगी। इन ट्रेनों का इस्तेमाल मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के निरीक्षण के लिए होगा। अभी इस कॉरिडोर का काम चल रहा है। ये दोनों ट्रेनें 2026 की शुरुआत तक भारत पहुंच जाएंगी। इन ट्रेनों से भारतीय इंजीनियरों को शिंकानसेन (ई5 शिंकानसेन) तकनीक को समझने में मदद मिलेगी। इससे कॉरिडोर के शुरू होने से पहले ही वे तकनीक से परिचित हो जाएंगे।

जीसीसी का रुख बदला

बहरीन, कुवैत और ओमान कतर से लेकर सऊदी अरब व यूएई भारत के साथ

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। भारतीय सांसदों का डेलीगेशन विभिन्न देशों की यात्रा पर है। भारत अपने मित्र देशों के यहां डेलीगेशन भेजकर पाकिस्तान की आतंकी करतूतों की लगातार पोल खोल रहा है। वैश्विक स्तर पर इससे पाकिस्तान की थू-थू होना शुरू हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की आतंकी सोच की जानकारी साझा करने के बाद संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से लेकर बहरीन, कुवैत व ओमान, कतर के रुख में भी व्यापक बदलाव आया है। आतंक के खिलाफ जंग में खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के इन सभी देशों ने भारत का साथ देने का वादा किया है।

10 लाख का इनामी नक्सली पप्पू लोहरा समेत दो ढेर

झारखंड में मुठभेड़, सुरक्षाबल का एक जवान घायल

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

रांची/लातेहार। झारखंड के लातेहार से बड़ी मुठभेड़ की खबर आ रही है. यहां 10 लाख के इनामी नक्सली को ढेर कर दिया गया है। वहीं, एक दूसरा नक्सली भी मारा गया है जो 5 लाख का इनामी बताया जा रहा है। इस मुठभेड़ में एक सुरक्षा बल का एक जवान भी घायल हुआ है। मारे गए नक्सली का नाम पप्पू लोहरा है जिस पर 10 लाख का इनाम था। इसके साथ ही प्रभात गंझू को भी मार गिराया गया है जिस पर 5 लाख रुपये का इनाम घोषित था। घायल हुए नक्सली संगठन के एक अन्य खूंखार नक्सली को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से एक इंसास राइफल बरामद

की गई है। ये सभी झारखंड मुक्ति परिषद के माओवादी के सदस्य हैं। जानकारी के अनुसार ऑपरेशन अभी भी जारी है।

नक्सलियों के खिलाफ इस वर्ष अभियान में मिली सफलता : इस वर्ष मिली नक्सलियों के खिलाफ सफलता : 24 मई को 10 लाख के इनामी पप्पू लोहारा समेत दो उग्रवादियों को लातेहार जिले में पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया। 21 अप्रैल को बोकारो के लुगू पहाड़ में 'ऑपरेशन डाकाबेड़ा' के तहत एक करोड़ के इनामी भाकपा माओवादी केंद्रीय कमेटी के सदस्य विवेक उर्फ प्रयाग मांझी, अरविंद यादव और 10 लाख के इनामी साहेब राम मांझी सहित 8 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। इसी फेहरिस्त के जनवरी 2025 में बोकारो जिले में 04 नक्सलियों को मार गिराया गया। इसमें एरिया कमांडर शांति देवी और मनोज टुडू को 21 जनवरी को बोकारो जिले में ढेर किया गया।

15 लाख का इनामी गिरफ्तार: रीजनल कमिटी मेंबर रणविजय महतो उर्फ रंजन को बोकारो से 21 जनवरी को गिरफ्तार किया गया। ये 15 लाख का इनामी नक्सली था।

पीएम कार्यक्रम को लेकर 26 को आएंगे मुख्य सचिव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 30 मई को प्रस्तावित है कार्यक्रम

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 मई को प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारी तेज हो गई है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए) के मैदान पर सुरक्षा के बीच जनसभा के लिए मंच और पंडाल तैयार किया जा रहा है। पीएम कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा करने प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह 26 मई, सोमवार को शहर आ रहे हैं। वे सुबह 10.40 बजे विवि के हेलीपैड पर उतरेंगे। यहां से वे पीएम कार्यक्रम की समीक्षा और स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसके बाद दोपहर दो बजे लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे।

पीएम मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप प्रदान करना शुरू कर दिया है। वर्तमान में सभी तैयारियां 24 अप्रैल को स्थगित हुए कार्यक्रम के अनुसार ही की जा रही हैं। अभी तक पीएमओ से किसी कार्यक्रम में बदलाव की कोई सूचना नहीं आई है। पीएम सिर्फ सीएसए विवि के मैदान पर जनसभा करेंगे।

यहां से 20 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। जिसमें मुख्य रूप से सेंट्रल स्टेशन से चुन्नीगंज के बीच अंडरग्राउंड मेट्रो, नियवेली पावर हाउस, पनकी पावर हाउस शामिल हैं। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक इन 11 परियोजनाओं में कुछ बदलाव संभव है। वहीं, पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिजनों से भी पीएम मोदी मुलाकात कर सकते हैं। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के कारण ही पीएम मोदी को 24 अप्रैल को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम स्थगित हुआ था। सीएसए विवि में साफ-सफाई का काम शुरू हो गया है। जनसभा स्थल पर पंडाल और मंच बनने से पहले सुरक्षाकर्मी बारीकी से जांच कर रहे हैं।

कल्याणपुर में देशभक्ति का ज्वार, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर निकली यात्रा

- वार्ड 35 उत्तरी में पार्षद आनंद शुक्ला के नेतृत्व में निकली भव्य तिरंगा यात्रा, ऑपरेशन सिंदूर की वीरगाथा बनी प्रेरणा
- वाहन पर सवार बाल वीरांगनाएं बनीं राष्ट्रभक्ति की प्रतीक, जगीं गर्व की लहरें-

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। भारतीय सेवा द्वारा संचालित ऐतिहासिक ऑपरेशन सिंदूर से प्रेरित होकर कानपुर के कल्याणपुर क्षेत्र के वार्ड 35 उत्तरी में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस गौरवशाली आयोजन का नेतृत्व क्षेत्रीय पार्षद आनंद शुक्ला ने किया, जबकि शुभारंभ कल्याणपुर विधानसभा की विधायक नीलिमा कटियार ने हरी झंडी दिखाकर किया।

यात्रा की शुरुआत सीएनजी पेट्रोल पंप, कल्याणपुर से हुई और पूरे वार्ड 35 में घूमती हुई टूटी पुलिया पर समाप्त हुई। भारत माता की जय, वंदे मातरम् और जय हिंद के नारों से गूंजती यह यात्रा क्षेत्रवासियों के लिए एक प्रेरणादायक दृश्य बन गई।

इस गौरवपूर्ण तिरंगा यात्रा की सबसे विशेष और ध्यान खींचने वाली झलक रही दो बालिकाओं की जीवंत उपस्थिति, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की मुख्य नायिकाओं कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह का रूप धारण किया हुआ था। ये दोनों बच्चियां यात्रा में शामिल एक वाहन पर सवार थीं, और उन्होंने राष्ट्रगौरव, नारी शक्ति और सैन्य शौर्य का प्रतीक बनकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।

उनके सैन्य परिधान और गंभीर, प्रेरणास्पद भाव-भंगिमाएं देख हर कोई नतमस्तक हो गया। जैसे ही यात्रा नगर की सड़कों से गुजरी, लोग रास्तों के किनारे खड़े होकर तिरंगे लहराते और उन बच्चियों को निहारते रहे। इस दृश्य ने न केवल देशभक्ति की भावना को बल दिया, बल्कि यह भी संदेश दिया कि भारत की बेटियाँ आज से ही नहीं, बल्कि भविष्य में भी राष्ट्र सेवा में अग्रणी रहेंगी।

सामाजिक और राष्ट्रप्रेमी चेहरों की सक्रिय भागीदारी

इस भव्य तिरंगा यात्रा में क्षेत्र के अनेक गणमान्य और राष्ट्रभक्त व्यक्तित्वों की उपस्थिति ने आयोजन को और अधिक गौरवशाली बना दिया। प्रमुख रूप से उपस्थित रहे

राजेश चंदेल, अनुज रजवत, राहुल शुक्ला, बृजेश तिवारी, मनीष दुबे, अनिल दीक्षित भाजपा जिलाध्यक्ष कानपुर पश्चिम, मनोज कालवानी, अर्पण शुक्ला, अनीता दीक्षित, संजू चौहान, और बड़े सिंह चंदेल।

भतीजों से अफेयर वाली चाची देखती थी गंदी फिल्में

» पति की हत्या में जेल जाने के बाद पुलिस ने मोबाइल देखा तो पुलिस कर्मियों के भी छूटे पसीने

» चाची का चल रहा था दो भतीजों से अफेयर

» आपत्तिजनक हालत में पकड़ी गई थी तो खुली पोल

पति की हत्यारोपी महिला

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। आज की डेट में रिश्तों की कोई गारंटी नहीं रह गई है. चलें तो सालों साल, वरना कभी भी खत्म. पति-पत्नी का रिश्ता यूं तो सात जन्मों का होता है, लेकिन कई कपल्स में अगर नहीं बने तो वो तलाक लेकर अलग रहने लगते हैं. मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तलाक के बजाय अपराध का रास्ता अपना लेते हैं. ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आया है. यहां एक चाची का अपने ही दो भतीजों के साथ चक्कर चल रहा था. पति ने जब एक भतीजे के साथ उसे आपत्तिजनक हालत में देख लिया तो वो डर गई. उसने फिर पति को ही मार डाला. इस हत्या में एक भतीजे ने चाची का साथ दिया. भतीजा मर्डर करने से डर रहा था, लेकिन चाची के कहने पर उसने उसका साथ दिया. अपने ही चाचा को चाची के साथ मिलकर मार डाला. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. चाची के मोबाइल को जब खंगाला गया तो पुलिस भी दंग रह गई. चाची गंदी फिल्में देखने की शौकीन निकली. उसके मोबाइल में 50 से भी ज्यादा गंदे वीडियो मिले. इसके अलावा वो रील बनाने की शौकीन है. पुलिस से बचने के लिए चाची ने सारे रील अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से डिलीट कर दिए थे. ताकि, पुलिस को दिखा सके कि उसके पास तो कोई मोबाइल है ही नहीं. लेकिन वो कहते हैं न कि अपराधी चाहे जितना भी शातिर हो, पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है. इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ. क्या है पूरी कहानी चलिए जानते हैं

यह खौफनाक घटना साढ़ इलाके के गांव लक्ष्मणखेड़ा की है. 32 साल का धीरेंद्र पासवान ट्रैक्टर चालक था और अपने परिवार के साथ लक्ष्मणखेड़ा गांव में रहता था. उसके परिवार में पत्नी रीना, 75 साल की बधिर मां और 4 साल का बेटा है. पास में ही धीरेंद्र का 23 वर्षीय भतीजा सतीश पासवान रहता था. रीना और सतीश के बीच लंबे समय से अवैध संबंध थे. रीना ने पुलिस को बताया कि एक दिन उसका पति उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में देख बैठा था. इसके बाद दोनों का मिलना-जुलना बंद हो गया.

पुलिस पूछताछ में रीना ने स्वीकार किया कि उसके और सतीश के बीच प्रेम संबंध थे. यही नहीं, वो एक और भतीजे अभिषेक से भी बातें करती थी. पति धर्मेंद्र ने सतीश के साथ उसे एक बार रंगे हाथों पकड़ा था और सतीश से मिलने पर पाबंदी लगा दी. जिसके बाद दोनों ने धर्मेंद्र की हत्या की योजना बनाई थी.

महिला ने पति धीरेंद्र को रास्ते से हटाने का सोच लिया था. उसने पति के खाने में नींद की गोलियां मिला दी. घटना वाली रात (10 मई) को रीना ने बढ़िया खाना बनाया पति को बढ़े ही चाव से खिलाया. धीरेंद्र ने पूरा खाना खाया और सोने के लिए चला गया. नींद की गोली वजह से धीरेंद्र पूरी तरह से बेहोशी की हालत में था.

पुलिस को रीना ने बताया कि जब उसका पति धीरेंद्र सो रहा था तो उसने भतीजे (प्रेमी) से हत्या करने के लिए कहा तो भतीजे जैसे ही चाचा की हत्या करने के लिए चला तो उसके हाथ पांव कांपने लगे. फिर रीना ने वहीं पास में पड़े घर के टूटे चौखट को उठाया और पति के सिर पर कई वार किए, जिससे धीरेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई. अब भतीजा और चाची दोनों जेल में बंद हैं.

युवती को ब्लैकमेल करने पर बीजेपी नेता व बेटे समेत तीन पर रिपोर्ट

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

उन्नाव। सदर कोतवाली क्षेत्र के एक भाजपा नेता व उसके बेटे समेत तीन पर आपत्तिजनक फोटो व वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर किशोरी को ब्लैकमेल करने की रिपोर्ट शुक्रवार को दर्ज की गई है। पीड़िता का आरोप है कि 70 हजार के जेवर आरोपियों ने लिए हैं।

» आपत्तिजनक फोटो व वीडियो को वायरल करने की धमकी

» सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर दी

सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर दी। बताया कि मगरवारा गांव निवासी भाजपा के पूर्व मंडल उपाध्यक्ष बीरू सिंह के बेटे कार्तिक ने सोशल मीडिया की मदद से उसकी नाबालिग बेटी से नजदीकियां बढ़ाईं। बाद में उसने मोबाइल से बेटी की आपत्तिजनक फोटो व वीडियो बना लिए। उन्हीं के जरिए आरोपी ने बेटी को ब्लैकमेल किया और जेवर की मांग की। न देने पर बदनाम करने के साथ ही परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इस पर सहमी बेटी ने युवक को करीब 70 हजार कीमत के जेवर सौंप दिए।

इसकी शिकायत जब भाजपा नेता से की गई तो उन्होंने मदद नहीं की, उल्टे गाली-गलौज कर भगा दिया। बताया कि बीरू सिंह अपने को भाजपा का पूर्व मंडल उपाध्यक्ष बताता है। वहीं, तहरीर के आधार पर पुलिस ने पिता पुत्र सहित तीन पर रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कार्तिक सिंह को पूछताछ के लिए उठाया तो उसने कचौड़ी गली निवासी सराफ को जेवर बेचने की बात बताई। पुलिस ने उसे भी उठाकर पूछताछ शुरू की है।

कोतवाल अवनीश सिंह ने बताया कि भाजपा नेता, उनके बेटे सहित तीन पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। तीसरे युवक पर आरोप है कि उसने आरोपी से पीड़िता की चेन खरीदी है। इसकी जांच चल रही है। जिस ज्वैलर्स की दुकान में जेवर बेचने की बात सामने आई है, उसके मालिक से भी पूछताछ की जा रही है।

हादसे में जान गंवाने वाली शिक्षिकाओं के उतार लिए जेवर !

सीएम पोर्टल से लेकर कमिश्नर तक की शिकायतें बेअसर, शिक्षिका के पति का दर्द बना असहनीय

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर । बीते 15 अप्रैल को जीटी रोड हाईवे पर नारामऊ कट के पास हुए सड़क हादसे में सफीपुर, उन्नाव की शिक्षिका अंजुला मिश्रा की जान चली गई। हादसे की सूचना पर पति आनंद मिश्रा जब पोस्टमॉर्टम हाउस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पत्नी के शरीर पर कोई गहना नहीं था, जबकि घर से निकलते वक्त वह सोने की चेन, अंगूठी, बिछिया और कान के बुंदे पहने थीं। आनंद ने बताया कि दुर्घटनास्थल से जो फोटो उन्हें मिले, उनमें भी पत्नी गहनों के साथ दिख रही थीं। लेकिन जब शव पोस्टमॉर्टम के लिए पहुंचा तो एक-एक कर सभी जेवर गायब हो चुके थे। यह स्थिति खुद पुलिस की मौजूदगी में बनी, जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है।

मृतका अंजुला मिश्रा की फाइल फोटो

थानों से लेकर पोर्टल तक दौड़ा पति, न सुनवाई न कार्रवाई

आनंद मिश्रा ने इस शर्मनाक घटना के खिलाफ कानपुर पुलिस कमिश्नर से लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल तक शिकायत की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि थाने में शिकायत देने के बावजूद किसी पुलिस अधिकारी ने उनसे संपर्क तक नहीं किया। सीएम पोर्टल पर की गई शिकायत भी पेंडिंग पड़ी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पत्नी के गहने इसलिए ढूंढवाने की कोशिश की क्योंकि वे न केवल उनकी निशानी थीं, बल्कि उनकी बेटियों के भविष्य के लिए सुरक्षित की गई थीं। 12 साल की सोनिमा और 6 साल की पर्णिका के सिर से मां का साया उठ गया, और अब मां की आखिरी निशानियों से भी वे वंचित कर दी गईं।

पुलिस की मौजूदगी में कैसे गायब हुए जेवर?

शव को घटनास्थल से लेकर मॉर्चुरी तक पुलिस की मौजूदगी में ले जाया गया, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह लापरवाही थी या फिर सुनियोजित चूक? एक वायरल ऑडियो में एक महिला और मौके पर मौजूद एक सिपाही की बातचीत सामने आई है, जिसमें सिपाही यह स्वीकार करता है कि वह अंजुला मिश्रा के शव के साथ एंबुलेंस में था। हालांकि, 'स्वराज इंडिया' इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। फिर भी, यह सवाल बना हुआ है कि अगर पुलिस बल साथ था तो गले से चेन, हाथ से अंगूठी, कान से बुंदे और पैर से बिछिया कैसे गायब हो गईं? एसीपी कल्याणपुर अभिषेक पांडेय ने मामले की जांच की बात जरूर कही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई। मृतका का परिवार अब मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाकर न्याय की गुहार लगाने की तैयारी में है।

जनप्रतिनिधि के खिलाफ ऑडियो प्रचलित,जांच शुरू

- बीएसए ने आनन फानन जारी किया चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का निलंबन आदेश
- सपा सरकार की राज्यमंत्री का करीबी बताया जा रहा है राहुल शुक्ला

स्वराज इंडिया संवाददाता

बिल्हौर(कानपुर)। एक क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि व उनके एक समर्थक के खिलाफ अभद्र बातचीत का आडियो शुक्रवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित होने के मामले में पुलिस ने जांच शुरू की है। आडियो की आवाज मिलान कर बेसिक शिक्षा विभाग के एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है। वहीं एक ग्राम प्रधान को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ की ।

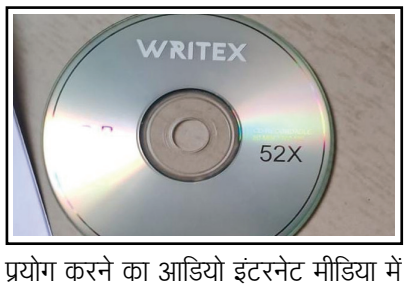

जानकारी के मुताबिक बिल्हौर में शुक्रवार को एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ अभद्र भाषा प्रयोग करने का आडियो इंटरनेट मीडिया में प्रचलित हुआ। इसमें बातचीत करने वाले व्यक्ति की आवाज का मिलान कर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि आडियो कुछ महीने पहले का बताया जा रहा है। मामले में उच्च प्राथमिक विद्यालय पूरा प्रथम में चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत कर्मचारी राधन गांव निवासी राहुल शुक्ला की तलाश शुरू की गई है। उसके खिलाफ बीएसए सुरजीत कुमार सिंह ने बिना देर किए निलंबन की कार्रवाई कर दी है। और उसे खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिल्हौर से संबद्ध कर दिया गया है। वहीं इस कार्रवाई को राजनीतिक चश्मे से भी देखा जा रहा है। जिसकी वजह राहुल शुक्ला की सपा शासन में राज्यमंत्री रही अरुणा कोरी से निकटता मानी जा रही है।

सम्पादकीय

राष्ट्रीय एकता के लिये चुनौती भाषाई टकराव

इसमें दो राय नहीं कि भाषाई विविधता रंग-बिरंगे फूलों की तरह भारत की खूबसूरती की वाहक है। वहीं यह विविधता देश की सांस्कृतिक समृद्धि का आधार भी है। यह विडंबना ही है कि राजनीतिक लाभ के लिये क्षेत्रीय भाषा के गौरव के नाम पर हिंदी विरोध का मोर्चा अकसर खोला जाता है। निस्संदेह समय-समय पर उभरने वाले विवाद क्षेत्रीय गर्व और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन बनाने की चुनौतियों को ही उजागर करते हैं। कुछ समय पहले ऐसे ही विवाद में मराठी को व्यवहार में न अपनाने के आरोप लगाकर एक अधिकारी को थप्पड़ मारने का विवाद सामने आया था। कालांतर भाजपा शासित राज्य में मराठी की अनिवार्यता कामकाज में लागू की गई थी। अब ताजा विवाद कर्नाटक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक प्रबंधक के कन्नड़ में बात करने से इनकार करने पर उठा है। जिसका कहना था कि वह हिंदी भाषी है और हिंदी में वार्तालाप करेगा। इस प्रकरण में अधिकारी का तबादला व खासा विवाद हुआ। स्वाभाविक रूप से क्षेत्रीय भाषा की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल खासे सक्रिय हुए। इस बीच जन सेवा में भाषाई संवेदनशीलता के प्रशिक्षण की मांग भी उठी। वैसे भी केंद्रीय सेवाओं के रूप में काम करने वाले विभागों व बैंक आदि के कर्मचारियों व अधिकारियों के विभिन्न राज्यों में अकसर तबादले होते रहते हैं। यह संभव भी नहीं कि हर व्यक्ति हर राज्य की भाषा बोल सके, लेकिन सीधे तौर पर जन-सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को राज्य की स्थानीय भाषा का ही उपयोग उपभोक्ताओं से सहज संवाद के लिये करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर बेंगलुरू में एक तकनीकी पेशेवर को हिंदी में बोलने के कारण पार्किंग की सुविधा से वंचित कर दिया गया। इस घटना ने गैर हिंदी भाषी इलाकों में भाषायी सहिष्णुता की बहस को नये सिरे से खड़ा किया। निश्चित रूप से दोनों ही घटनाएं भाषाई व सांस्कृतिक एकता के लिये चुनौती पेश करती हैं। जिस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।उल्लेखनीय है कि ये घटनाएं राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 के त्रि-भाषा फार्मूले की पृष्ठभूमि में हुई हैं। दरअसल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में छात्रों को तीन भाषाएं सीखने की सलाह दी गई है। जिसमें कम से कम दो भारत की मूल भाषाएं होनी चाहिए। हालांकि, इस शैक्षिक नीति का मकसद बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना है,लेकिन तमिलनाडु में इस नीति का प्रतिरोध सामने आया है। राजनीतिक दल इसे हिंदी थोपने और अपनी भाषाई पहचान के लिये खतरा बता रहे हैं। तमिलनाडु में हिंदी को लेकर विरोध की राजनीति का पुराना इतिहास रहा है। खासकर तब से जब हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की कवायद शुरू हुई थी। हालांकि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लचीलेपन के साथ इस बात पर जोर देती रही है कि किसी भी राज्य पर कोई भाषा नहीं थोपी जाएगी। इसके साथ यह भी कि भाषाओं के चयन का मुद्दा राज्य, क्षेत्रों और छात्रों पर छोड़ दिया जाएगा। वहीं कतिपय राजनीतिक दल आरोप लगाते रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा का व्यावहारिक क्रियान्वयन एक विवादस्पद मुद्दा है। बहरहाल, इस मुद्दे पर क्षेत्रीय भाषाओं पर इसके प्रभाव और हिंदी के कथित प्रभुत्व को लेकर बहस चल रही है। बहरहाल, इस तरह के विवादों से आगे बढ़ने के लिये आपसी सम्मान और समझ का माहौल बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है। सार्वजनिक संस्थानों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उनकी सेवाएं स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराई जाएं। इसके साथ ही कर्मचारियों व अधिकारियों को सांस्कृतिक और भाषाई संवेदनशीलता में प्रशिक्षित किया जाए।

सुरक्षा में रणनीतिक गेम चेंजर बनी ब्रह्मोस

अमित तिवारी

हालिया सैन्य कार्रवाई में भारत ने सटीकता से लक्ष्य नष्ट करने में सक्षम ब्रह्मोस मिसाइल सुखोई एमकेआई-30 से छोड़ी। हमले का मकसद हासिल कर पायलटों के लिए न्यूनतम जोखिम यकीनी बनाया। कम ऊंचाई पर उड़ान व सुपरसोनिक क्रूज प्रोफ़ाइल ने इसकी श्रेष्ठता सिद्ध की। तकनीकी युद्धक तरीकों के चलते ब्रह्मोस रणनीतिक गेम चेंजर बन रही है।

महायुद्ध के दौरान वायु सेना के महारथी कहा करते थे कि हवाई ताकत स्वाभाविक रूप से आक्रामक होती है और इसको अपना काम करने की पूरी छूट होनी चाहिए, जीत के लिए हवाई युद्ध में श्रेष्ठता होना आवश्यक है; बमवर्षक दुश्मन की रक्षा में सेंध लगा देते हैं और इसके बाद रणनीतिक बमबारी के जरिए उसकी इच्छाशक्ति को तोड़ा जा सकता है। हालिया सैन्य कार्रवाई में, भारतीय वायु सेना द्वारा हवा से प्रक्षेपित ब्रह्मोस का समायोजन सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू विमान से करने की सार्थकता फिर पुष्टि करती है कि यह सिद्धांत अभी भी उतना ही सही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान युद्ध विराम का अनुरोध करने को मजबूर हुआ।

1983 में, भारत सरकार ने एकीकृत गाइडेड मिसाइल विकास कार्यक्रम का गठन किया। शुरुआत में यह बैलिस्टिक मिसाइलों पर केंद्रित था। लेकिन 1991 के खाड़ी युद्ध के दौरान इराकी वायु रक्षा प्रणालियों पर अमेरिकी युद्धपोतों और हवाई जहाजों से प्रक्षेपित टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों के विनाशकारी प्रभाव ने भारत को इसका दायरा बढ़ाने को प्रेरित किया। साल 1998 में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने रूसी समकक्ष के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत ब्रह्मोस एयरोस्पेस संयुक्त उद्यम की स्थापना की गई। साल 2001 में ब्रह्मोस का पहला टैस्ट लॉन्च किया गया।ब्रह्मोस एक दो-चरणीय क्रूज मिसाइल है, जिसके प्रथम चरण प्रकोष्ठ में एक ठोस प्रोपैलेंट बूस्टर भरा रहता है, जो मिसाइल को सुपरसोनिक (आवाज की गति) बना देता है। अपना काम पूरा करने के बाद, इस प्रकोष्ठ के अलग होने के उपरांत, आगे की उड़ान एक तरल-ईंधन चालित रैमजेट इंजन से होती है। जो इसे मैक-3 (ध्वनि की गति से तीन गुणा) जितनी क्रूज़िंग रफ्तार प्रदान करता है। यह मिसाइल 15 किमी की ऊंचाई लेकर महज 10 मीटर के बीच उड़ान भर सकती है और इसकी कार्य सीमा 300-800 किमी तक हो सकती है। यह 200-300 किलोग्राम तक का पारंपरिक वारहेड (विस्फोटक) ले जा सकती है और 'फायर-एंड-फॉरगेट' सिद्धांत पर काम करती है। दागे जाने के बाद, यह इनर्शियल नेविगेशन, उपग्रहीय मार्गदर्शन और इलाके की भूगोलीय रूपरेखा के मिलान का उपयोग करके अपने लक्ष्य तक स्वायत्त रूप से पहुंचती है, और एक मीटर से भी कम की सटीकता से वार करने में समर्थ है।हवा-से-सतह पर मार करने वाला इसका संस्करण 2017 में बना और इसे 2020 में स्काड्रन 222, टाइगर शार्क्स में शामिल किया गया था। ब्रह्मोस को इसकी परम गति, सटीकता और गतिज प्रभाव सबसे घातक पारंपरिक क्रूज मिसाइलों में से एक बनाती है। ब्रह्मोस की गति से बनने वाले सीधे प्रबलित प्रहार का आघात गहरे बंकरों, युद्धपोतों या कमांड सेंटर तक को नष्ट कर सकता है। इसकी गतिज यानी काइनैटिक ऊर्जा अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइल से 32 गुना अधिक है। जैसे-जैसे थल आधारित वायु रक्षा प्रणालियां अधिक सटीक एवं घातक होती जा रही, हवाई माध्यम (लड़ाकू विमान) को अपने काम को अंजाम देने में जो स्वतंत्रता पहले कभी हासिल थी, वह कम होती जा रही है। यूक्रेन-रूस युद्ध इसका जीवंत उदाहरण है। शुरुआती चरणों में अपने-अपने विमान बेड़े का भारी नुकसान उठाने के बाद, दोनों पक्षों ने युद्धग्रस्त क्षेत्रों में उड़ान भरने से परहेज करने और लंबी दूरी के हवाई हथियारों पर भरोसा करना शुरू किया।यही तरीका हालिया भारत-पाक टकराव में देखने को मिला। न तो भारतीय और न ही पाकिस्तानी लड़ाकू विमान एक-दूसरे देश की वायु सीमा में दाखिल हुए। पाकिस्तानी हमलों में ज्यादा निर्भरता तुर्किये निर्मित ड्रोनों पर रही, जिनमें अधिकांश मार गिराये गये। पाकिस्तान ने 'फतह' नामक बैलेस्टिक मिसाइल का भी उपयोग किया। इन बैलिस्टिक मिसाइलों का राडार क्रॉस-सेक्शन मार्क अधिक होता है ।

चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी-समावेशी बनाने का प्रयास

ईपीआईसी नंबर डुप्लिकेशन समस्या

डॉ. जगदीप सिंह

नये वोटर आईडी बनाने का कदम मतदाता सूची की विश्वसनीयता सुदृढ़ करेगा, मतदान प्रक्रिया सुगम बनाएगा और चुनावी धोखाधड़ी रोकने में मदद करेगा। राजनीतिक दृष्टिकोण से, यह आयोग की निष्पक्ष छवि को पुनर्स्थापित कर सकता है तथा विपक्षी दलों की रणनीतियां प्रभावित कर सकता है।

भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में मतदाता सूची में इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी ईपीआईसी नंबरों की डुप्लिकेशन समस्या को हल करने के लिए नए पहचान पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय लगभग दो दशक पुरानी एक तकनीकी समस्या को संबोधित करता है, जिसमें विभिन्न राज्यों के मतदाताओं को गलती से एक जैसे ईपीआईसी नंबर आवंटित हो गए थे। इसके परिणामस्वरूप मतदान के दौरान भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई, कुछ मत अमान्य घोषित किए गए, और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगने लगे।

ईपीआईसी नंबर, जिसे आमतौर पर वोटर आईडी के रूप में जाना जाता है, भारतीय मतदाताओं की पहचान का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह प्रत्येक मतदाता को मतदाता सूची में एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है, जो निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। निर्वाचन आयोग ने इस समस्या के समाधान के लिए नए और अद्वितीय ईपीआईसी नंबरों के साथ मतदाता पहचान पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। यह कदम मतदाता डेटाबेस को अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस निर्णय का प्रभाव केवल तकनीकी सुधार तक सीमित

नहीं रहेगा, बल्कि यह भारतीय राजनीति और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को भी सुदृढ़ करेगा। डुप्लिकेट ईपीआईसी नंबरों की समस्या ने मतदाता सूची की सटीकता पर गंभीर प्रश्न खड़े किए थे। नए पहचान पत्रों के जारी होने से मतदाता डेटाबेस अधिक विश्वसनीय और पारदर्शी बन सकेगा, जिससे निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता और कार्यक्षमता को बल मिलेगा तथा मतदाताओं का विश्वास और बढ़ेगा। पूर्व में, डुप्लिकेट ईपीआईसी नंबरों के कारण कई मतदाताओं को मतदान करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, और कुछ मामलों में उनके मत अमान्य कर दिए जाते थे। अब, नए और अद्वितीय ईपीआईसी नंबरों के माध्यम से मतदाताओं को अपनी पहचान सत्यापित करने में सुविधा होगी, जिससे मतदान प्रक्रिया अधिक सुचारु और समावेशी बन सकेगी। यह भविष्य में अन्य तकनीकी सुधारों— जैसे आधार से मतदाता सूची को जोड़ने या बायोमेट्रिक सत्यापन को लागू करने — के लिए आधार प्रदान कर सकता है। साथ ही, यह निर्णय चुनावी धोखाधड़ी, जैसे फर्जी मतदान, को रोकने में सहायक सिद्ध होगा।ईपीआईसी नंबर डुप्लिकेशन का मुद्दा हाल के महीनों में राजनीतिक विवाद का केंद्र रहा है। इस समस्या के समाधान से आयोग अपनी साख में सुधार ला सकता है और राजनीतिक दलों के बीच विश्वास पुनः स्थापित कर सकता है। हालांकि, कुछ दल इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास करते रह सकते हैं, लेकिन अब यह मुद्दा पहले की तुलना में कम प्रासंगिक रहेगा।यह निर्णय मतदाता सूची और संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इससे राजनीतिक दलों और नागरिक समाज को व्यापक चुनावी सुधारों, जैसे मतदाता सूची का डिजिटलीकरण, पारदर्शी मतदान प्रणाली, और ईवीएम-वीवीपैट की विश्वसनीयता पर विमर्श के लिए प्रेरणा मिल सकती है।हालांकि यह निर्णय सकारात्मक दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन इसके प्रभावी क्रियान्वयन में अनेक चुनौतियां होंगी। विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज़ के क्षेत्रों में नए ईपीआईसी कार्डों का वितरण एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है। साथ ही, मतदाताओं को नए कार्डों के बारे में जागरूक करना और पुराने कार्डों को अमान्य करने की प्रक्रिया को भी प्रभावी ढंग से लागू करना होगा। भविष्य में, निर्वाचन आयोग को ऐसी समस्याओं से बचने के लिए और अधिक सुदृढ़ तकनीकी समाधानों—जैसे ब्लॉकचेन आधारित मतदाता डेटाबेस या बायोमेट्रिक एकीकरण — पर विचार करना चाहिए। साथ ही, राजनीतिक दलों और नागरिकों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखना आवश्यक है।

26 मई सोमवार को मनाई जाएगी

वट सावित्री व्रत

वटवृक्ष से मांगे सौभाग्य का वरदान

ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस बार वट सावित्री व्रत यानी बरगदाही 26 मई सोमवार को है। ज्योतिषाचार्य एसएस नागपाल ने बताया कि सावित्री ने यमराज से पति सत्यवान के प्राण छुड़ाकर पुनजीर्वित करा लिया था। अखंड सुहाग की कामना से सुहागिनें व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्माजी, तने में विष्णु जी और डालियों व पत्तियों में भगवान शिव का वास माना जाता है। अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई को दोपहर 12 : 11 बजे से 27 मई को सुबह 8 : 31 बजे तक रहेगी। ज्येष्ठ अमावस्या को तिथि दोपहर के समय में वट वृक्ष का पूजन करना श्रेष्ठ है। वट सावित्री व्रत के दिन चन्द्रमा कृतिका नक्षत्र और मेष राशि में दिन में 1.40 तक रहेगा। इसके उपरान्त वृषभ राशि का संयोग बना रहे है। बुध आदित्य योग और मालव्य योग भी बनेगा।

व्रत विधान- प्रात :काल स्नान आदि के बाद बांस की टोकरी में सप्त धान्य रख कर ब्रह्मा जी की मूर्ति की स्थापना कर फिर सावित्री की मूर्ति की स्थापना करते हैं। दूसरी टोकरी में सत्यवान और सावित्री की मूर्तियों की स्थापना करके टोकरी को वट वृक्ष के नीचे जाकर ब्रह्मा, सत्यवान व सावित्री की पूजा करके वट (बरगद) की जड़ में जल देते हैं। वट वृक्ष (बरगद) के नीचे बैठ कर सावित्री और सत्यवान की कथा भी सुननी चाहिए। पूजन विधि–पूजा में जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भीगा चना, फूल तथा धूप से पूजन करते है। वट वृक्ष पूजन में तने पर कच्चा सूत लपेट कर 7, 21 अथवा 108 परिक्रमा का विधान है लेकिन न्यूनतम सात बार परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए।

बीजेपी विधायक की कार से विधानसभा पास हुआ गायब, एफआईआर दर्ज

कार सर्विसिंग के दौरान हुआ पास चोरी का मामला, विधायक ने जताई दुरुपयोग की आशंका, सर्विस सेंटर प्रबंधन पर उठे सवाल

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर । गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी की टोयोटा फॉर्च्यूनर कार से उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी आधिकारिक पास रहस्यमय ढंग से चोरी हो गया है। यह घटना उस समय सामने आई जब विधायक ने अपनी कार सर्विसिंग के लिए कानपुर के 'सनी टोयोटा' सर्विस सेंटर में जमा कराई थी।

विधायक के अनुसार, उन्होंने अपनी गाड़ी (यूपी 78 FF 1111) को 17 मई की सुबह 11 बजे नियमित सर्विस के लिए एनएच-2, रूमा औद्योगिक क्षेत्र स्थित सर्विस सेंटर में जमा कराया था। जब 21 मई की शाम गाड़ी वापस मिली, तो उस पर विधानसभा पास गायब था।

मैथानी ने इस संबंध में महाराजपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है और बताया कि सर्विस सेंटर की ओर से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह स्पष्ट हुआ है कि जब गाड़ी सर्विस सेंटर में दाखिल हुई थी, तब पास गाड़ी पर चस्पा था, लेकिन बाहर निकलते समय वह नहीं था।उन्होंने पास के दुरुपयोग की आशंका जताते हुए कहा कि इस तरह के पास का प्रयोग आपराधिक गतिविधियों या संगठित अपराध में किया जा सकता है, जो राज्य की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। विधायक ने सर्विस सेंटर प्रबंधन को इस पूरे घटनाक्रम का जिम्मेदार ठहराया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और सर्विस सेंटर के सीसीटीवी फुटेज की भी गहनता से समीक्षा की जा रही है।

चौबेपुर में तिरंगा शौर्य यात्रा का हुआ आयोजन

» यात्रा में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनता ने उत्साह पूर्वक शिरकत कर क्षेत्र के माहौल को देशभक्ति पूर्ण बना दिया

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

चौबेपुर । कानपुर नगर के चौबेपुर ब्लाक में ब्लॉक प्रमुख राजेश शुक्ला की अगवाई में तिरंगा शौर्य यात्रा का आयोजन हुआ। तिरंगा शौर्य यात्रा बंदी माता तिराहा से अमर शहीद नित्यानंद स्मारक तक निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनता ने उत्साह पूर्वक शिरकत कर क्षेत्र के माहौल को देशभक्ति पूर्ण बना दिया। हाथों में तिरंगा लिए हजारों लोग एक स्वर में हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों से क्षेत्र को गुंजायमान कर रहे थे। बहुत से लोग तिरंगे के साथ अपने हाथों में विभिन्न प्रकार के जोशीले स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर चल रहे थे। यात्रा का समापन अमर शहीद नित्यानंद के स्मारक पर हुआ। जहां ब्लॉक प्रमुख राजेश शुक्ला ने तिरंगा यात्रा के विषय में लोगों को बताया और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना को बधाई दी। समापन के समय जिला अध्यक्ष उपेंद्र पासवान ने यात्रा में सम्मिलित लोगों के उत्साह की भूरि भूरि प्रशंसा करते हुए भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में दिखाए गए अदम्य शौर्य व साहस पर प्रकाश डाला।

5 दिन से किशोरी गायब, कार्रवाई के नाम पर खामोश बैठी रनिया पुलिस

शिवांग अग्निहोत्री/स्वराज इंडिया

कानपुर देहात । थाना रनिया क्षेत्र के ग्राम उमरन से 18 मई को एक 16 वर्षीय किशोरी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई। परिजनों ने उसी दिन थाना रनिया में पहुंचकर तहरीर दी और गांव के ही कुछ युवकों पर साजिश के तहत किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने का आरोप लगाया। इसमें मुख्य आरोपी सुनील यादव पुत्र ज्ञान सिंह और उसके सहयोगी मुनेश, गुलाब, फूल सिंह व सुमित के नाम स्पष्ट रूप से तहरीर में दर्ज हैं।

एसपी और एडिशनल एसपी के आदेश फेल, रनिया पुलिस की लापरवाही ने बढ़ाई पीड़ित परिवार की पीड़ा

पुलिस ने 19 मई को मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन इसके बाद कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया। परिजनों का कहना है कि पांच दिन बीतने के बावजूद पुलिस ने आरोपियों से न कोई पूछताछ की, न ही कोई दबिश दी। ऐसे में उन्हें अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता है। इस लापरवाही के चलते पीड़िता का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है, जबकि आरोपियों को खुलेआम गांव में देखा जा रहा है।

अधिकारियों से दो-दो बार गुहार, पर लापरवाही बरकरार

घटना के बाद पीड़िता के परिजनों ने 20 मई को कानपुर देहात के पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की थी, जिसमें पूरे मामले की गंभीरता से जानकारी दी गई और आरोपियों की गिरफ्तारी व किशोरी की बरामदगी की मांग रखी गई। एसपी ने तत्काल कार्रवाई का आश्वासन देते हुए रनिया थाने को निर्देश भी दिए, लेकिन इसके बाद भी थाना स्तर पर कोई ठोस पहल नहीं की गई।

इसके बाद बीते दिन परिजन एडिशनल एसपी से भी मिले और उन्हें घटना की पूरी जानकारी दी। एडिशनल एसपी ने भी सख्त कार्रवाई का आश्वासन देते हुए स्थानीय पुलिस को आदेशित किया कि मामले को प्राथमिकता देते हुए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और किशोरी को शीघ्र बरामद किया जाए। इसके बावजूद रनिया पुलिस का रवैया अब भी लापरवाह और निष्क्रिय बना हुआ है। परिजनों का कहना है कि जब जिले के दोनों वरिष्ठ अधिकारी कार्यवाही के निर्देश दे चुके हैं, तब भी यदि थाने की पुलिस सक्रिय नहीं हो रही, तो यह गंभीर चिंता का विषय है। थाने की इस सुस्ती ने न सिर्फ पीड़ित परिवार को मानसिक रूप से तोड़ दिया है, बल्कि गांव के अन्य लोगों में भी पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर गहरी नाराजगी है।

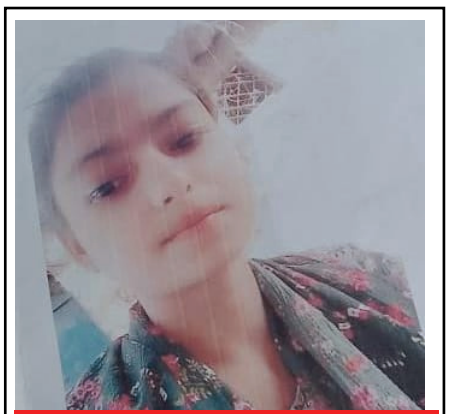
गायब किशोरी

मुख्य आरोपी सुनील यादव

बंद हुई रजबहे की खांधी, किसानों ने ली राहत की सांस

स्वराज इंडिया संवाददाता

कानपुर देहात । घाटमपुर रजवाहा बलवा हर के सामने तीन दिनों से चल रही खांधी की समस्या से ग्रामीण बेहद परेशान थे। यह खांधी उमरन में बनी झील को भरने के लिए खोली गई थी, जिससे आसपास के किसानों की फसलें और जनजीवन प्रभावित हो रहा था।

ग्रामीणों ने अपनी समस्या स्वराज इंडिया समाचार पत्र के मुख्यालय संवाददाता सचिन सिंह चौहान से साझा की, जिसके बाद 25 मई को पृष्ठ संख्या 9 पर इस मुद्दे को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। खबर छपते ही गंगनहर विभाग ने संज्ञान लिया और रजवाहा पर तैनात कर्मचारियों को तत्काल खांधी बंद करने के निर्देश जारी कर दिए।

समस्या का समाधान होते ही ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और स्वराज इंडिया अखबार का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह अखबार हमेशा गरीब, असहाय व किसानों की आवाज को प्रमुखता से उठाता है, इसीलिए यह जन-जन का लोकप्रिय माध्यम बन चुका है।

» स्वराज इंडिया अखबार की खबर के बाद हरकत में आया गंगनहर विभाग, ग्रामीणों ने जताया आभार

घाटमपुर के पास रजवाहा फटने से कई गांव जलमग्न, सिंचाई विभाग बना मूकदर्शक

उमरन झील भरने के नाम पर रोकी गई खांधी, न पानी आगे पहुंच रहा, न गांवों का बच रहा नुकसान

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। घाटमपुर क्षेत्र के बलवा हर गांव के पास रजवाहा की पटरी फटने से भारी जलभराव की स्थिति बन गई है। बीते तीन दिनों से लगातार बहते पानी ने पांच गांवों को जलमग्न कर दिया है और करीब 500 बीघा फसल बर्बाद हो चुकी है। ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग को कई बार सूचना दी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाही नहीं हुई है। विभागीय लापरवाही के चलते मूंग की खड़ी फसल और चारे की बुवाई पानी में डूब चुकी है, जिससे किसानों में भारी आक्रोश है।

ग्रामीणों का कहना है कि अफसर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि गांववाले खुद पटरी बांध दें। वहीं, गंग नहर विभाग द्वारा छोड़ा गया पानी उमरन झील भरने के लिए खांधी के माध्यम से डायवर्ट किया जा रहा है, जिसके कारण आगे रजवाहा सूखा पड़ा है और अन्य तालाब पानी को तरस रहे हैं। सवाल यह उठ रहा है कि क्या उमरन झील भरने के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है?

क्या बोले जिम्मेदार

सिंचाई विभाग के एसडीओ ओमप्रकाश दिनकर से संपर्क नहीं हो सका। वहीं विभाग के जेई ने बताया कि उमरन की करीब 100 एकड़ झील को भरा जा रहा है, इसलिए खांधी को बंद नहीं किया जा सकता। झील भरते ही पटरी की मरम्मत कर दी जाएगी।

ग्रामीणों की पीड़ा और अधिकारियों की उदासीनता ने एक बार फिर यह उजागर कर दिया है कि सरकारी तंत्र आमजन की तकलीफों से कितना दूर है।

रजबहे की पटरी में मिट्टी डालती जेसीबी मशीन

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सपना देवी द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। **संपादक:** अनूप कुमार **RNI No.:** UPHIN/2023/86769 | **Email:** swarajindia2023@gmail.com | **Mob:** 7800009853, | **Website:** www.swarajindianews.com | (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे)

प्रधान की दबंगई से विकास कार्य ठप

शौचालय तीन साल से बंद, अधिकारियों की अनदेखी से जनता में आक्रोश

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। उत्तर प्रदेश सरकार जहां गांव-गांव में विकास की गंगा बहाने के लिए दिन-रात प्रयासरत है, वहीं भोगनीपुर ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान की अड़ियल मानसिकता और भाजपा विरोधी रवैये के चलते सरकारी योजनाएं दम तोड़ रही हैं। मुख्यमंत्री द्वारा 2022 में भोगनीपुर चौराहे पर बनाए गए शौचालय को बने तीन वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अब तक उसमें ताला ही लटका है। नाली सफाई हो या खड़ंजा निर्माण, आवास योजना हो या अन्य जनहितकारी काम–किसी भी कार्य में प्रधान रुचि नहीं ले रहे हैं। ग्रामीणों की बार-बार की शिकायत के बावजूद कोई समाधान नहीं निकल रहा। ग्राम प्रधान न केवल शिकायतों को नजरअंदाज कर रहे है, बल्कि शिकायतकर्ताओं को धमकाने से भी बाज नहीं आ रहे।

अधिकारियों की चुप्पी बनी सवाल

ब्लॉक अमरौधा के एडीओ पंचायत राम प्रकाश पाठक ने स्वीकारा कि ग्राम प्रधान उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, जबकि बार–बार निर्देश दिए जा चुके हैं। इससे साफ है कि ब्लॉक स्तर तक ही कामकाज सिमट कर रह गया है और जमीनी हकीकत पूरी तरह उपेक्षित है। जिम्मेदार अधिकारियों की निष्क्रियता और प्रधान की दबंगई से गांव का विकास रुका हुआ है। जनता अब शासन–प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे धरना–प्रदर्शन जैसे कदम उठाने को मजबूर होंगी।

स्वराज इंडिया www.swarajindianews.com कानपुर देहात कानपुर शुक्रवार 23 मई, 2025 08

साढ़े तीन साल से अधूरा पड़ा शौचालय

मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और डीएम के आदेशों के बावजूद नहीं खुला ताले में बंद सामुदायिक शौचालय, करोड़ों खर्च का हिसाब अधूरा, खुले में शौच को मजबूर ग्रामीण

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। भोगनीपुर चौराहे पर वर्षों से लंबित सामुदायिक शौचालय निर्माण का मामला सरकार की तमाम योजनाओं और निर्देशों की पोल खोल रहा है। वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और तत्कालीन जिलाधिकारी नेहा जैन ने महिलाओं की सुविधा को देखते हुए तत्काल शौचालय निर्माण के निर्देश दिए थे। प्रशासन ने आदेश के पालन में अधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंपी, लेकिन ढाई साल बीत जाने के बाद ... अधूरा है या ताले ...

स्थानीय लोगों का ... है कि चौराहे पर महिलाओं और यात्रियों को खुले में शौच ... पड़ता है, जिससे आए दिन शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। स्वच्छ भारत मिशन की असलियत इस अधूरे निर्माण से सामने आ गई है, और यह मामला अब केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार की बू देने लगा है।

-निर्माण में भारी गड़बड़झाला, जांच भी दबा दी गई

शौचालय निर्माण में नरेगा श्रमिकों से काम करवा कर पेमेंट बाहरी मजदूरों के नाम से उठाया गया। सूत्रों के मुताबिक, शौचालय की दीवारें पुरानी खुदाई की ईंटों से बनाई ... जबकि बजट में नई ईंटें ... ये खर्च दर्शाए गए। ... पर जिला स्तरीय जांच ... जिसमें अनियमितताएं उजागर हुईं, लेकिन आज तक किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। गांव की महिलाओं और सामाजिक संगठनों का कहना है कि शौचालय तैयार होने के बावजूद जनता के लिए नहीं खोला गया ताकि फर्जी बिल और पेमेंट का खेल चलता रहे। सवाल यह है कि जब शासन से लेकर जनप्रतिनिधि तक आदेश दे चुके हैं, तब भी ब्लॉक, ग्राम पंचायत और संबंधित अधिकारियों की चुप्पी क्यों? यह शौचालय अब जनहित की जरूरत नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार की नजीर बनता जा रहा है।

नोडल अधिकारी ने जल जीवन मिशन योजना का देखा हाल

बनार अलीपुर गांव में जल गुणवत्ता और पाइपलाइन कार्यों को लेकर दिए दिशा-निर्देश

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव एवं जनपद के नोडल अधिकारी हरिकेश चौरसिया ने ग्राम बनार अलीपुर में जल जीवन मिशन के तहत कराए गए कार्यों का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाइपलाइन बिछाने, जल टंकी की स्थिति, सोलर पैनल, घरेलू नल कनेक्शन और जल की गुणवत्ता की जानकारी ली।

लाभार्थी उषा के घर से पानी मंगाकर वॉटर टेस्टिंग किट से जांच भी की गई। नोडल अधिकारी ने कार्य की गुणवत्ता पर संतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि शुद्ध व नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए और समय-समय पर जल की जांच भी की जाती रहे।

जनसहभागिता और जागरूकता पर दिया जोर

निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारी ने ग्रामीणों और अधिकारियों से संवाद स्थापित कर योजना के प्रभाव को समझा। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य हर घर में नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है। भ्रमण के दौरान उन्होंने रोड रेस्टोरेशन कार्यों को भी देखा और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि जल संरक्षण के प्रति जागरूक रहें और योजना की सफलता में भागीदार बनें। साथ ही यह आश्वासन भी दिया कि जहां–जहां सुधार की आवश्यकता होगी, वहां शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण में जल निगम, ग्राम विकास विभाग व जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।

नालसा साथी अभियान को लेकर जिला स्तर पर बनाई जा रही रणनीति

18 वर्ष से कम आयु के निराश्रित बच्चों को शासकीय योजनाओं से जोड़ने का निर्देश

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में, जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात तेजप्रताप तिवारी के कुशल निर्देशन में नालसा साथी अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। अभियान का उद्देश्य 18 वर्ष से कम आयु के निराश्रित बच्चों का सर्वेक्षण कर उन्हें आधार कार्ड से जोड़ना और शिक्षा, स्वास्थ्य, कानूनी सहायता समेत विभिन्न शासकीय लाभकारी योजनाओं से लाभान्वित करना है।

दिनांक 22.05.2025 को अपर जिला जज/नामित सचिव हिमांशु कुमार सिंह द्वारा अभियान की सुचारू क्रियान्वयन हेतु गठित समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मौजूद समस्त तहसीलदार (कानपुर देहात), तहसीलदार घाटमपुर व बिल्हौर (कानपुर नगर), बाल सुरक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक के जिला समन्वयक सहित अन्य समिति सदस्यों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे चिन्हित बच्चों को अपने–अपने विभाग की योजनाओं से जोड़ना सुनिश्चित करें।

यह अभियान न केवल संवेदनशीलता का परिचायक है, बल्कि बच्चों के समग्र विकास की दिशा में एक सशक्त पहल भी है।

कसरैलाडीह गांव: मेहंदी लगाए बैठी रही दुल्हन, नहीं पहुंची बारात

लड़की के पिता का आरोप है कि दहेज में एक लाख रुपये और अपाचे मोटरसाइकिल की मांग की थी

स्वराज इंडिया संवाददाता

सिरौलीगौसपुर बाराबंकी। कसरैलाडीह गांव में एक विवाह समारोह में दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा। साहब दीन की बेटी लक्ष्मी का विवाह रामनगर क्षेत्र के बिठौरा निवासी जगदीश के बेटे लवलेश से तय हुआ था।लवलेश ने दहेज में एक लाख रुपये और अपाचे मोटरसाइकिल की मांग की थी। लड़की के पिता साहब दीन यह मांग पूरी नहीं कर पाए। लक्ष्मी ने बताया कि वह लवलेश से लगातार संपर्क में थी। लवलेश बारात लाने का आश्वासन दे रहा था।

23 मई को बारात आने की तिथि थी। दुल्हन के घर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। खान-पान और साज-सज्जा की व्यवस्था की गई थी। रिश्तेदार भी आ चुके थे। दुल्हन के हाथों में मेहंदी लग चुकी थी। विवाह से पहले की सभी रस्में पूरी हो चुकी थीं।

जब बारात नहीं पहुंची तो परिवार ने जानकारी जुटाई। दूल्हे पक्ष ने बताया कि लवलेश बीमार है और अस्पताल में भर्ती है।

लक्ष्मी के पिता ने बताया कि उन्होंने कई महीनों से शादी की तैयारियां की थीं। उन्होंने कर्ज लेकर दहेज का सामान जुटाया था।

परिवार ने रात में पुलिस को सूचना दी। पीआरबी पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया। लक्ष्मी पांच भाई-बहनों में सबसे छोटी बहन है। इस घटना से पूरा परिवार दुखी है।

सिरौलीगौसपुर के बदोसराय में दहेज की मांग को लेकर एक महिला को प्रताड़ित करने और तीन तलाक देने का मामला सामने आया है। पीड़िता शबीना बानो की शिकायत पर पुलिस ने पति मोहम्मद नसीम समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

शबीना की शादी 22 फरवरी 2022 को सफदरगंज के पंडरा निवासी नसीम से हुई थी। उनके दो बच्चे हैं। ढाई साल का बेटा और 9 महीने की बेटी वर्तमान में पिता के पास हैं।

15 मई को रात साढ़े नौ बजे ससुराल वालों ने दहेज में दी गई एचएफ डीलक्स बाइक को कम बताते हुए बुलेट मोटरसाइकिल और दो लाख रुपए की मांग की। मना करने पर पति, सास सलीमुन, जेठ मोहम्मद इम्तियाज, ननद सकीना और नन्दोई साबिर ने मिलकर शबीना की पिटाई की। पति ने उसका गला भी दबाया।

मोहल्ले वालों की मदद से शबीना के परिजनों को बुलाया गया। जब उसके माता-पिता

पहुंचे, तब वह बेहोश थी। इसके बाद पति ने सबके सामने तीन तलाक दे दिया।

शबीना ने 16 मई को थाने में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 21 मई को दोबारा शिकायत दर्ज कराई गई। पीड़िता के पिता निसार अहमद खेती करते हैं। 2014 में एक दुर्घटना के बाद से वह दिव्यांग हैं। उनकी पांच बेटियों में शबीना दूसरे नंबर पर है। अभी तीन बेटियों और दो बेटों की शादी होनी बाकी है।

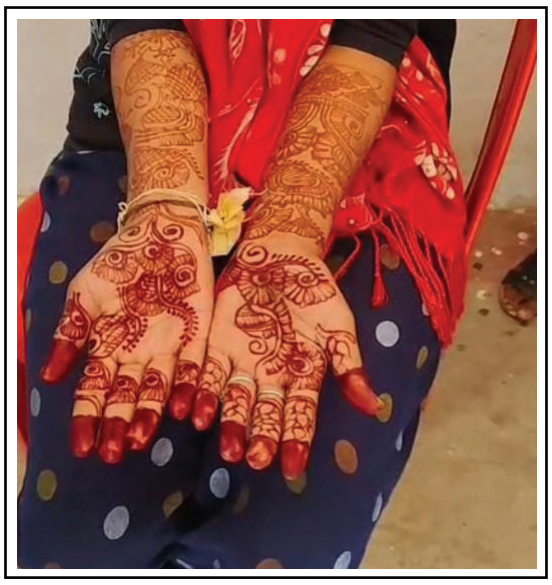

मासूम के साथ हैवानियत की कोशिश

पास्को और दुष्कर्म के संग अन्य गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है

स्वराज इंडिया संवाददाता

सूरतगंज बाराबंकी । थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में पड़ोसी के घर शादी कार्यक्रम से एक पांच वर्षीय बच्ची को गांव का पच्चीस वर्षीय युवक जबरन मुंह बंद कर उठा ले गया। जिसके बाद गांव के बाहर एक बाग में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। जिसके बाद नशे में धुत युवक ने सारी हदें पार कर बहुत ही गंदा काम करने की कोशिश की उसकी इस दरिदंगी से गांव में आक्रोश भी व्याप्त है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। पास्को और दुष्कर्म के संग अन्य गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

मोहम्मदपुर खाला क्षेत्र थानांतर्गत सूरतगंज चौकी के एक गांव में गुरूवार की शाम एक शादी समारोह कार्यक्रम आयोजित हो रहा था। सभी अपने काम में व्यस्त थे तभी गांव का सौरभ कुमार वहां पहुंचा और बच्ची को अकेला देखकर मुंह दबाकर उसे उठा ले गया। गांव के बहार एक बाग में पहुंच उसने पहले दुष्कर्म के प्रयास किए।

सफल न होने पर, युवक ने उसके योनि में उंगलियां और हाथ डालने की दरिदंगी की। उधर गायब हुई बच्ची की खोज करके जब परिवार वाले वहां पहुंचे तो वह दर्द से तड़प रही थी।

ऐसा हाल देख घर वाले उसे आनन फानन में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सूरतगंज पहुंचे जहां पर डाक्टरों ने उपचार के बाद, उसे घर भेज दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।वहीं थाना प्रभारी निरीक्षक जगदीश प्रसाद शुक्ला ने बताया, आरोपी नशे का आदी भी है,न्यायालय में पेश किया गया था कि आरोपी को वहां से उसे जेल रवान किया गया है।

शहीद लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार

» माँ की आंखों में बस एक ही सवाल था. क्या अब वो लौटेगा?

» सेना और जनप्रतिनिधियों ने दी श्रद्धांजलि

स्वराज इंडिया संवाददाता

अयोध्या। मझवा गद्दोपुर गांव आज खामोश था,हर चेहरा उदास, हर दिल भारी। गांव का लाल, लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी अब सिर्फ तस्वीरों में मुस्कुरा रहा है। सिक्किम में तैनाती के दौरान जब साथियों की जान खतरे में थी, शशांक ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्हें बचा लिया–और खुद शहीद हो गया।

कल शाम जब सेना की गाड़ी उनका पार्थिव शरीर लेकर गांव पहुंची, तो चारों ओर सिर्फ एक ही गूंज थी–शशांक अमर रहें! माँ बेसुध थीं, पिता की आंखें पत्थर हो चुकी थीं और गांव का हर बच्चा उसे अपना हीरो कह रहा था।

शनिवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। सेना के जवानों ने बंदूकों की सलामी दी, और हर किसी की आंखों से आंसू बह निकले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहायता और एक सरकारी नौकरी की घोषणा की।

गांव वालों ने कहा ऽशशांक सिर्फ हमारा नहीं, पूरे देश का बेटा था। वो चला गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया एक ऐसी कहानी, जो आने वाली पीढ़ियों को सिखाएगी कि देशभक्ति क्या होती है।

राजनीति का शिकार हुई सब सेंटर तहसीनपुर की स्टाफ नर्स

» बेगुनाह होने के बावजूद मिली सजा

» सीएमओ ने सब सेंटर से हटाया, दिए जांच के निर्देश

स्वराज इंडिया संवाददाता

अयोध्या। सीएचसी सोहावल के आरोग्य सेंटर तहसीनपुर में तैनात स्टाफ नर्स राजनीति का शिकार बन गईं। सीएमओ ने स्टाफ नर्स को उस गुनाह की सजा दे दी जो उसने किया ही नहीं। सीएमओ ने एक ऐसी शिकायत को सज्ञान में ले लिया जिसका कोई आधार बनता ही नहीं है।

मिली जानकारी के अनुसार सोहावल तहसील के सफीपुर गाँव निवासी कुलदीप की पत्नी सबिता को चार माह का गर्भ था। गुरुवार को अचानक उसको पेट में काफी पीड़ा होने लगी। सविता अपना उपचार कराने के लिए आरोग्य सेंटर तहसीनपुर पहुंची। उस समय वहाँ स्टाफ नर्स विनीता गुप्ता मौजूद नहीं थी। सेंटर पर मौजूद दाई ने सबिता को सीएचसी सोहावल जो सेंटर से मात्र तीन किमी है, जाने की राय दी। उस समय सेंटर पर मौजूद एक आशा बहू ने सविता के पति को फोन कर यह जानकारी दी कि उसकी तबियत खराब है। सबिता को तत्काल सीएचसी सोहावल या जिला महिला अस्पताल ले जाएं।सब सेन्टर से बाहर जाने के बाद सबिता का चार माह का गर्भपात हो गया।

इस मामले को सबिता के पति ने नर्स की लापरवाही बताते हुए सीएमओ से जांच कराने की मांग की थी। उसने स्टाफ नर्स पर हत्या का मुकदमा भी दर्ज कराने की मांग की थी। हालांकी सीएमओ ने नर्स को देवगांव के लिए स्थानांतरित कर दिया है और जांच के निर्देश दिए हैं। फिर भी लोग इस मामले को राजनीति मानकर यह कह रहे हैं, नर्स राजनीति का शिकार हुई है।

सब सेंटर पर नहीं होती गर्भपात कराने की कोई व्यवस्था

सब सेंटर पर गर्भपात से सम्बन्धित उपचार की कोई व्यवस्था नहीं हौती। यह कहना है स्त्री रोग विशेषज्ञ व सीएचसी अधीक्षक डा फातिमा हसन का। उन्होंने बताया कि सबिता को भयंकर पेट दर्द होने का कारण उसके गर्भपात की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। दाई ने हमें भी बताया था कि बच्चेदानी का मुंह खुल रहा था। सीएचसी आने पर सही ढंग से उपचार हो सकता था। उन्होंने यह पूछने पर कि गर्भपात किस वजह से हो सकता है। डा0 फातिमा ने बताया कि कभी कभी नेचुरल हो जाता है। अधिकतर ऐसी कंडीशन गर्भपात की दवा का सेवन करने से भी हो सकता है। गिरने या चोट लगने। गर्भ के दौरान पपीता का सेवन कर लेने से या भारी वस्तु उठा लेने से ऐसी स्थिति बन सकती है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि घटना के समय नर्स टीकाकरण के कागजात जमा कराने सीएचसी आई थी।

तहसीनपुर उपकेंद्र पर लटका ताला

अयोध्या। सामुदायिक स्वास्थ केंद्र सोहावल अंतर्गत तहसीनपुर उपकेंद्र पर लटका ताला स्वास्थ विभाग द्वारा सूचना पट्ट पर नोटिस चस्पा किया गया है। प्रसव हेतु आई हुई महिलाओं को सूचित किया जाता है। बता दे कि एएनएम का हो गया है स्थानांतरण देवगांव प्रसव हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोहावल पहुंच कर प्रसव कराए। जिले के दूसरे स्थान पर प्रसव कराने में टॉपटेन रहने वाले उपकेंद्र तहसीनपुर में कब तक लगा रहेगा ताला अपने आप में बड़ा सवाल है।

दो वीडियो हुए थे वायरल

रिश्वतखोरी का आरोपी अधिशासी अभियंता निलंबित

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बरेली। विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता (33 केवी वर्टिकल) महावीर सिंह को प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल ने निलंबित कर दिया है। निलंबन के दौरान महावीर सिंह को मुख्य अभियंता (वितरण) अयोध्या के कार्यालय से संबद्ध किया गया है। अधिशासी अभियंता के रिश्वत लेते हुए दो वीडियो वायरल हुए थे। प्रथम दृष्टया जांच में उन्हें दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने और निगम की छवि धूमिल करने का दोषी पाया गया है।

अधिशासी अभियंता महावीर सिंह का 17 मई को एक वीडियो वायरल हुआ था। यह वीडियो उसके कार्यालय का ही था। इसमें वह विद्युत निगम के ठेकेदार नाजिम से एक लाख रुपये लेते दिख रहा है। हालांकि, ठेकेदार ने यह कहकर उसे बचाने की कोशिश की थी कि उसने यह रुपये उधार लिए थे जो बाद में लौटा दिए। मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश ने जांच के लिए दो सदस्यों की कमेटी बना दी। जांच पूरी होने से पहले ही 21 मई को महावीर सिंह का एक और वीडियो वायरल हुआ। इसमें वह फाइल पर हस्ताक्षर करने के बदले लिफाफा लेता दिख रहा है। कर्मचारियों के साथ अशोभनीय व्यवहार का भी आरोप है। वायरल वीडियो और अन्य शिकायतों का संज्ञान लेते हुए प्रबंध निदेशक ने उस पर कार्रवाई कर दी।

यूपी के मुख्य सचिव को एनएचआरसी कोर्ट से नोटिस

कई आदेशों के बावजूद कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किये प्रमाण

» प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

- यूपी मुख्य सचिव एनएचआरसी कोर्ट में तलब हुए, पेशी से छूट मांगी, पर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया, कोर्ट ने जारी किया रिमाइंडर, किया सख्त कार्रवाई के लिए आगाह
- 105 साल पुरानी कानपुर पुलिस लाईन बैरक ढह जाने से मृतक और घायल पुलिस कर्मियों के न्याय के लिये शहर के पंकज कुमार सिंह की याचिका पर एनएचआरसी कोर्ट में चल रही सुनवाई

लखनऊ/ नई दिल्ली। सरकार सुशासन के बड़े बड़े दावे जरूर कर ले लेकिन उसके दरबार में ही कोर्ट के आदेशों को दरकिनार किया जाये तो सूबे में लॉ एण्ड आर्डर के पालन और कानून का राज का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ऐसे में कोई अपने उवाच ज़ाहिर भी कर दे तो उसके जहन में कार्रवाई का भय घर कर जाता है।

यह हम नहीं कह रहे यह जनता के बीच से उठी आवाज़ को हम समाचार के रूप में आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि 105 साल पुरानी कानपुर पुलिस लाईन बैरक ढह जाने से मृतक और घायल पुलिस कर्मियों के न्याय के लिये शहर के पंकज कुमार सिंह की याचिका पर एनएचआरसी कोर्ट में चल रही है, इन सुनवाई की तारीखों की प्रोसीडिंग देखिये तो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य अधिकारी यानी मुख्य सचिव अपने ही मातहतों के न्याय के लिए कितने संजीदा हैं वो पिछले चार साल से अधिक समय से एनएचआरसी कोर्ट की तरीख-दर-तारीख और कोर्ट के जारी सम्मन से समझा जा सकता है।

एनएचआरसी कोर्ट द्वारा जारी सशर्त सम्मन के जवाब में, सरकार सचिव, द्वारा दिनांक 18.11.2024 की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। यूपी सरकार ने इसमें कहा है कि मृतक की पत्नी और तीन घायलों को मुआवजा देने का मामला विचाराधीन है, जिसमें अभी और वक्त लगने की संभावना है. उन्होंने रिपोर्ट सौंपने के लिए दो महीने का और समय देने की प्रार्थना की। उन्होंने मुख्य सचिव,सरकार की एनएचआरसी के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने का भी अनुरोध किया। जिसे स्वीकार कर समय दिया गया। एनएचआरसी कोर्ट ने मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन और अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को रुपये के अनुशंसित मुआवजे के वितरण पर की गई कार्रवाई पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

अनुसरण में, एसपी (एचआर), लखनऊ, उत्तर प्रदेश को संबोधित उप सचिव के दिनांक 08.04.2025 के एक आंतरिक पत्र सहित विभिन्न संचार प्राप्त हुए हैं, जिसमें कहा गया है कि मृतक कांस्टेबल अरविंद कुमार सिंह की पत्नी को 20,00,000/- रुपये और मां को 5,00,000/- रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया था, हालांकि भुगतान का प्रमाण पत्र के साथ संलग्न नहीं किया गया है। इसके अलावा, आयोग के निदेशानुसार तीन घायल कर्मियों- हेड कांस्टेबल अमृत लाल, कांस्टेबल राकेश और कांस्टेबल मनीष कुमार में से प्रत्येक को25,000/- रुपये की अंतरिम सहायता के संबंध में कोई जानकारी प्रदान नहीं की गई है। साथ ही मृतक के आश्रितों को मिलने वाले ई-पेमेंट की रसीद भी गायब है. कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। यह मामला एनएचआरसी कैंप बैठक के दौरान समीक्षा किए जाने वाले सात लंबित मामलों में से एक है।एनएचआरसी कोर्ट ने सख्त लहज़े में आदेश किया है कि सरकार के मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, को एक नया अनुस्मारक जारी किया जाए। मृतक पुलिस कर्मी और घायलों के मुआवजा राशि के भुगतान का प्रमाण छह सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा ऐसा न करने पर यह आयोग पीएचआर अधिनियम की धारा 13 के तहत अपनी जबरदस्त शक्तियों को लागू करने के लिए बाध्य होगा।

पुलिस कर्मियों के न्याय के लिए लड़ रहे पंकज एक आम नागरिक की प्रतिक्रिया पुलिस के प्रति कैसी भी हो लेकिन कानपुर के सोशल एक्टिविस्ट और पेशे से इंजीनियर पंकज कुमार सिंह पुलिस हित में लगातार सक्रियता में रहते है। वे पुलिस कर्मियों और उनके परिजनों के इलाज़ के लिए कैशलेस व्यवस्था के लिए भी उच्च पर कार्रवाई के लिए सक्रीय हैं। उनका कहना है कि विपरीत परिस्थियों में पुलिसकर्मी लोकसेवा में तैनात रहते है उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रयास करना और जिम्मेदारों तक बात पहुँचाना हमारा कर्तव्य है। मैं यह मानता हूं कि पुलिसकर्मी हमारी पुलिस व्यवस्था की रीढ़ होते हैं। यही वे लोग हैं जो दिन-रात कानून और व्यवस्था बनाए रखते हैं। उनका जीवन सुरक्षित और सम्मानित होना हमारा सामाजिक और संवैधानिक कर्तव्य है। इसलिए हम पुलिस के न्याय के सक्रियता में हैं, क्योंकि न्याय सिफ़्र आम नागरिक का नहीं, बल्कि हर वर्दीधारी का भी अधिकार है।

केरल में 8 दिन पहले पहुंचा

खूब बरसेंगे बादल देश में आज मॉनसून ने दे दी दस्तक

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। गर्मी से जूझ रहे देशवासियों के लिए आईएमडी ने गुड न्यूज दी है। मौसम विभाग के अनुसार आज केरल में मॉनसून से दस्तक दे दी है। इस बार मॉनसून वक्त से 8 दिन पहले ही केरल पहुंच गया है।

केरल में दक्षिण-पश्चिम में मॉनसून ने समय से पहले ही धमाकेदार दस्तक दे दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक, मॉनसून ने अपनी सामान्य तारीख 1 जून से 8 दिन पहले आज केरल की धरती को भिगोना शुरू कर दिया। आखिरी बार इतनी जल्दी मॉनसून 2009 में आया था, जब 23 मई को बादलों ने केरल में डेरा डाला था। मॉनसून ने आठ दिन पहले ही केरल में दस्तक दे दी है, जिसके बाद अब इसके मुंबई में 10-15 जून तक मॉनसून के पहुंचने की उम्मीद है, जबकि दिल्ली में ये 25-30 जून तक दस्तक दे सकता है। हालांकि, शुरुआती आगमन का मतलब यह नहीं है कि पूरे देश में बारिश का पैटर्न एकसमान होगा। मौसम विभाग के विशेषज्ञों का कहना है कि मॉनसून की प्रगति क्षेत्रीय और वैश्विक मौसमी कारकों पर निर्भर करती है।

गाजियाबाद में 4 नए मरीज मिले

कोरोना केस में उछाल, राजधानी में अस्पतालों के लिए एडवाइजरी जारी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। देश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। दिल्ली हरियाणा गुजरात केरल समेत कई राज्यों में कोविड-19 के मामले सामने आए हैं जिनमें दिल्ली में 23 मामले शामिल हैं। सरकार अस्पतालों में बेड और दवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने में जुटी है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है सरकार स्थिति से निपटने के लिए तैयार है।

देश की राजधानी दिल्ली में अभी तक कोरोना वायरस के 23 मामले सामने आ चुके हैं. स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी मामलों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और सभी हॉस्पिटल्स को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निदेज़्श दिए गए हैं. दक्षिण भारत में कोरोना वायरस के लगातार केस बढ़ते ही जा रहे हैं इसी बीच राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी कोरोना के संक्रमण ने दस्तक दे दी है. वैश्विक स्तर पर लगातार कोरोना वायरस के बढ़ते केस की वजह से स्वास्थ्य विभाग की चिताएं बढ़ गई हैं. भारत में कम गति के साथ इसके केस में बढ़ोत्तरी हो रही है. अभी तक कोरोना के कुल एक्टिव केस देश में 350 तक पहुंच गए हैं. वहीं दिल्ली की बात करें तो 23 एक्टिव केस सामने आ चुके हैं. गाजियाबाद में कुल 4 एक्टिव केस सामने आए हैं. दिल्ली एनसीआर में कोरोना के मामले बढ़ने से फ्लिहाल स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारियों में जुट गया है और स्थिति पर नजदीकी से नजर रखी जा रही है।

स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त करने के दिए निर्देश

दिल्ली के सभी 23 एक्टिव मामलों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. सभी हॉस्पिटल्स से संपर्क किया जा रहा है और स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने बताया कि जो मामले बढ़े हैं उनमें प्राइमरी रिपोटज़् में सामान्य इन्फ्लूएंजा की जानकारी मिली है।

यहां कोविड-19 के केस : उत्तर प्रदेश में 4, कर्नाटक में 16, केरल में 95, तमिलनाडु में 66, पुडुचेरी में 10, पश्चिम बंगाल में 1 और सिक्किम में 1 केस मिले।

भीम आर्मी ने किया बवाल

अस्पताल की फर्श पर लगाई भगवान बुद्ध और अंबेडकर की टाइल्स

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

आगरा। आगरा थाना हरिपर्वत क्षेत्र के एक निजी अस्पताल की फर्श पर भगवान बुद्ध और डॉ भीमराव अंबेडकर वाली टाइल्स लगाए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है।

आगरा के एक निजी अस्पताल में भगवान बुद्ध और डॉ भीमराव अंबेडकर वाली टाइल्स फर्श पर लगाने का मामला सामने आया है. जब इस बात की जानकारी अंबेडकर के अनुयाई, बसपा और भीम आर्मी के कार्यकताओं को हुई तो उन्होंने अस्पताल पहुंचकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पाकर इलाकाई पुलिस भी मौके पर पहुंची। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच नोकझोक भी देखने को मिली है।

प्रदर्शनकारियों ने दिया 3 दिन का अल्टीमेटम : प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर अस्पताल संचालक पर 3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारी भी थाना हरी पर्वत पहुंचे, जहां सभी कार्यकताओं को कार्रवाई का आश्वासन दिया है।